



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 368]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 5, 2015/ज्येष्ठ 15, 1937

No. 368]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 2015 /JYAISTHA 15, 1937

पोत परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2015

सा.का.नि. 459(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नौवहन महानिदेशालय और वाणिज्यिक समुद्री विभाग, समूह-‘क’ (सामुद्रिक) पद भर्ती नियम, 2003 को, जहां तक उनका संबंध नॉटिकल सलाहकार, प्रधान अधिकारी (सामुद्रिक), उप नॉटिकल सलाहकार और नॉटिकल सर्वेक्षक के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुये जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पोत परिवहन मंत्रालय के नौवहन महानिदेशालय और वाणिज्यिक समुद्री विभाग में समूह-‘क’ (सामुद्रिक) पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पोत परिवहन मंत्रालय, नौवहन महानिदेशालय और वाणिज्यिक समुद्री विभाग, समूह-‘क’ (सामुद्रिक) पद भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना- ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान - उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु- सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।

5. निरर्हता - वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु - सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) सामुद्रिक सलाहकार भारत सरकार- सह अपर महानिदेशक (सामुद्रिक)	1*(2015) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है) ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय ।	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी(एचएजी) ₹67,000- 79,000/-.	चयन।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि ।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।

(11)

प्रोन्नति :

ऐसे प्रधान अधिकारी (सामुद्रिक) जिन्होंने वेतन बैंड-4, ₹37,400 – 67000/- + ग्रेड वेतन ₹10,000 की श्रेणी में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा की है और जिसके पास निम्नलिखित अर्हताएं हैं :

(i) अतिरिक्त मास्टर का प्रवीणता प्रमाणपत्र; या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा समुद्री कार्य में प्रदान की गई एम.एस.सी. की डिग्री ।

(11)

(ii) विदेशगामी पोत पर मास्टर की क्षमता में एक वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 : प्रोन्नति के लिए स्तम्भ (11) में यथा विहित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के लिए नौवहन महानिदेशालय कार्यालय, पोत परिवहन मंत्रालय खर्च वहन करेगा और पोषक प्रवर्ग के पदधारियों को सुविधा प्रदान करेगा।

टिप्पण 2 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हता/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 3 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरिक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जायेगी।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या लोक क्षेत्र का उपक्रम या अर्ध सरकारी या कानूनी, या स्वायत्त शासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :

(क) (i) जो अपने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने वेतन बैंड-4- ₹37,400 – 67,000/ + ग्रेड वेतन ₹10,000 या समतुल्य श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा की है ; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव है :

(i) अतिरिक्त मास्टर का प्रवीणता प्रमाणपत्र सहित विदेशगामी वाणिज्यिक पोतों और ऐसे पोतों पर लगे पोत उपस्करों के सर्वेक्षण और निरीक्षण में 12 वर्ष का अनुभव; या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई समुद्री कार्य में एम.एस.सी. की डिग्री सहित विदेशगामी वाणिज्यिक पोतों और ऐसे पोतों पर लगे पोत उपस्करों के सर्वेक्षण और निरीक्षण में 15 वर्ष का अनुभव।

(ii) विदेशगामी पोत के मास्टर के रूप में प्रवीणता प्रमाण-पत्र सहित डैक अधिकारी के रूप में 5 वर्ष की सेवा जिसमें से विदेशगामी पोत पर एक वर्ष मास्टर की क्षमता के रूप में कार्य किया हो।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नत द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरिक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरिक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद/उन पदों पर विस्तारित होगा, जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण ग्रेड प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष; (2) सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय -सदस्य; (3) नौवहन महानिदेशक -सदस्य।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा शामिल है) द्वारा भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(2) प्रधान अधिकारी (सामुद्रिक)-सह-संयुक्त महानिदेशक (तकनीकी)।	2* (2015) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन बैंड - 4 ₹37,400-67,000 + ग्रेड वेतन ₹10,000	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है।

(11)
<p>प्रोन्नति :</p> <p>(1) ऐसा उप सामुद्रिक सलाहकार-सह-वरिष्ठ उप महानिदेशक (तकनीकी) जो वेतन बैंड - 4, ₹37,400 – 67000 के साथ ₹8,700/- ग्रेड वेतन की श्रेणी में कम से कम 3 वर्ष की नियमित सेवा की है और जिसके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं हों :</p> <p>(i) अतिरिक्त मास्टर का प्रवीणता प्रमाणपत्र; या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई समुद्री कार्य में एम.एस.सी. की डिग्री।</p> <p>(ii) विदेशगामी पोत पर मास्टर की क्षमता में एक वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1 : प्रोन्नति के लिए स्तम्भ (11) में यथा विहित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के लिए नौवहन महानिदेशालय कार्यालय, पोत परिवहन मंत्रालय खर्च लागत करेगा और पोषक प्रवर्ग के पदधारियों को सुविधा प्रदान करेगा।</p> <p>टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हता/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 3 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरिक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जायेगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है)</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान या अर्ध सरकारी या कानूनी, या स्वायत्तशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :</p>

(11)

(क) जो अपने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं: या

जिन्होंने वेतन बैंड -4- ₹37,400 – 67,000/- + ग्रेड वेतन ₹ 8700 या समतुल्य श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है: और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।

(i) विदेशगामी पोत के मास्टर के रूप में प्रवीणता प्रमाण-पत्र सहित डैक अधिकारी के रूप में 5 वर्ष की सेवा जिसमें से विदेशगामी पोत पर एक वर्ष मास्टर की क्षमता के रूप में कार्य किया हो।

(ii) अतिरिक्त मास्टर का प्रवीणता प्रमाणपत्र सहित विदेशगामी वाणिज्यिक पोतों और ऐसे पोतों पर लगे पोत उपस्करों के सर्वेक्षण और निरीक्षण में दस वर्ष का अनुभव; या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई समुद्री मामलों में एम.एस.सी. की डिग्री सहित विदेशगामी वाणिज्यिक पोतों और ऐसे पोतों पर लगे पोत उपस्करों के सर्वेक्षण और निरीक्षण में 12 वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नत द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद/उन पदों पर विस्तारित होगा, जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण ग्रेड प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)	(13)
<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <p>(1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष;</p> <p>(2) सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय -सदस्य;</p> <p>(3) नौवहन महानिदेशक -सदस्य।</p>	<p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा शामिल है) द्वारा भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(3) उप सामुद्रिक सलाहकार – सह-वरिष्ठ उप-महानिदेशक (तकनीकी)	5* (2015) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन बैंड -4 ₹37,400-67,000 + ग्रेड वेतन ₹8,700।	चयन।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा

(11)

प्रोन्नति :

ऐसा नॉटिकल सर्वेक्षक – सह – उप-महानिदेशक (तकनीकी) जिसने वेतन बैंड – 3, ₹15,600 – 39,100 + ग्रेड वेतन ₹7,600 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और जो निम्नलिखित शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं रखता है :

- अतिरिक्त मास्टर का प्रवीणता प्रमाण-पत्र ; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई समुद्री मामलों में एम.एस.सी. की डिग्री ।
- विदेशगामी पोत पर मास्टर की क्षमता में एक वर्ष का अनुभव ।

टिप्पण 1 : प्रोन्नति के लिए स्तम्भ (11) में यथा विहित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के लिए नौवहन महानिदेशालय कार्यालय, पोत परिवहन मंत्रालय खर्च वहन करेगा और पोषक प्रवर्ग के पदधारियों को सुविधा प्रदान करेगा।

टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हता/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से , इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण 3 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरिक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जायेगी ।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- <ol style="list-style-type: none"> (1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष; (2) सचिव या अपर सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय - सदस्य; (3) नौवहन महानिदेशक - सदस्य; (4) संयुक्त सचिव, नौवहन का भारसाधक, पोत परिवहन मंत्रालय - सदस्य । 	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(4) सामुद्रिक सर्वेक्षक-सह-उप-महानिदेशक (तकनीकी)	21* (2015) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है) ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन बैंड – 3, ₹15,600- 39,100/- + ग्रेड वेतन ₹7,600	लागू नहीं होता ।	50 वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख से अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय,

					अरुणाचल प्रदेश, मिजोराम, मणिपुर, नगालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप खंड तथा अंदमान निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
--	--	--	--	--	--

(7)	(8)
<p>आवश्यक :</p> <p>(i) भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विदेशगामी पोत के मास्टर के रूप में प्रवीणता-प्रमाण पत्र।</p> <p>(ii) द्वितीय मेट (विदेशगामी) का प्रवीणता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद डेक अधिकारी के रूप में 5 वर्ष की सेवा, जिसमें से विदेशगामी पोत पर एक वर्ष मास्टर के रूप में कार्य किया हो।</p> <p>वांछनीय :</p> <p>(i) अतिरिक्त मास्टर का सक्षमता प्रमाणपत्र; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई समुद्री कार्य में एम.एस.सी. की डिग्री।</p> <p>(ii) संघ लोक सेवा आयोग में आवेदन किये जाने की तारीख को वाणिज्यिक पोतों का सर्वेक्षण और निरीक्षण करने तथा परीक्षा कार्य का एक वर्ष या अधिक का अनुभव</p> <p>टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2 : अनुभाव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है। जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>	लागू नहीं होता।

(9)	(10)	(11)
एक वर्ष।	<p>सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>टिप्पण : पदधारी की प्रतिनियुक्ति लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्न अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी।</p> <p>(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन बैंड 3, ₹15,600-39,100 तथा ग्रेड वेतन ₹66,00 में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) स्तंभ (7) के अधीन विहित शैक्षिक अर्हताएं ओर अनुभव रखते हैं।</p>	लागू नहीं होता।

(12)	(13)
<p>समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <p>(1) नौवहन महानिदेशक - अध्यक्ष;</p> <p>(2) संयुक्त सचिव, नौवहन का भारसाधक, पोत परिवहन मंत्रालय -सदस्य;</p> <p>(3) संयुक्त महानिदेशक, प्रशासनिक कार्य का भारसाधक, नौवहन महानिदेशालय -सदस्य।</p>	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[सं. ए-12018/2/2007-एमए]

सी. बी. सिंह, सलाहकार

MINISTRY OF SHIPPING**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th June, 2015.

G.S.R.459(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate General of Shipping and Mercantile Marine Departments Group 'A' (Nautical) Posts Recruitment Rules, 2003, in so far as they relate to the posts of Nautical Adviser, Principal Officer (Nautical), Deputy Nautical Adviser and Nautical Surveyor, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Group 'A' (Nautical) in the Ministry of Shipping, Directorate General of Shipping and Mercantile Marine Department, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Shipping, Directorate General of Shipping and Mercantile Marine Department, Group 'A'(Nautical) Posts Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.- These rules shall apply to the posts specified in the column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.-The number of said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in the columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in the columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such a person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.-Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by an order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules, with respect to any class or category of persons.

7. Saving.-Nothing contained in these rules shall affect the reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-Serviceman and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1.) Nautical Adviser to the Government of India – cum – Additional Director General (Nautical)	1* (2015) *(Subject to variation dependent on work load).	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial.	Higher Administrative Grade (HAG) - Rs.67,000-79,000/-	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation including short term contract.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grade from which recruitment by promotion or deputation/absorption is to be made.

(11)

Promotion:

Principal Officer (Nautical) with minimum three years regular service in the pay band-4, Rs. 37,400-67,000 plus grade pay of Rs. 10,000/- and possessing the following qualifications:

(i) Extra Master's Certificate of Competency; or

Master of Science Degree in Maritime Affairs awarded by a recognised University.

(ii) experience of one year in capacity of a Master on a Foreign going ship

Note 1: For acquiring educational qualification as prescribed in column (11) for promotion, the Office of Directorate General of Shipping, Ministry of Shipping shall bear the cost and facilitate the incumbents in the feeder grade post.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Commission.

Deputation (including short-term contract)

Officers of the Central Government or the State Government or Union Territory Administration or recognised Universities or recognised Research Institutions or Public Sector Undertaking or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations :

(A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band-4, Rs. 37400-67000 + grade pay of Rs. 10000/- or equivalent in the parent cadre or department; and

(B) possessing the following educational qualification and experience:

(i) Extra Master's Certificate of Competency with twelve years experience in survey and inspection of foreign going merchant ships and equipments on board such a ship; or

Master of Science Degree in Maritime Affairs awarded by a recognised University with fifteen years experience in survey and equipments on board such a ship;

(ii) Certificate of Competency as Master (Foreign Going Ships) with five years experience as Deck Officer of which one year must have been in the capacity of a Master on a foreign going merchant ship.

Note 1: The Departmental Officers in the feeder grade who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short-term contract). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years.

Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.

Note 4: For the purpose of appointment on deputation (including short-term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission's recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).
(1) Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman;	
(2) Secretary, Ministry of Shipping – Member;	
(3) Director General of Shipping – Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(2.) Principal Officer (Nautical)-cum-Joint Director General (Technical).	<u>2* (2015)</u> *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band - 4 Rs.37400-67000 plus grade pay of Rs. 10000/-.	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation Including short term contract.

(11)
<p>Promotion:</p> <p>(1) Deputy Nautical Advisor-cum-Senior Deputy Director General (Technical) in Pay Band-4, Rs. 37400-67000/- with Grade Pay of Rs.8,700/-, with minimum three years regular service in the grade and possessing the following educational qualifications:</p> <p>(i) Extra Master's Certificate of Competency; or</p> <p>Master of Science Degree in Maritime Affairs awarded by a recognized University.</p> <p>(ii) experience of one year in capacity of a Master on a Foreign going ship.</p> <p>Note 1: For acquiring educational qualification as prescribed in column (11) for promotion, the Office of Directorate General of Shipping, Ministry of Shipping shall bear the cost and facilitate the incumbents in the feeder grade post.</p> <p>Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Commission.</p>

Deputation (including short-term contract)

Officers of the Central Government or the State Government or Union territory Administration or recognised Universities or recognised Research Institutions or Public Sector Undertaking or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations :

(A) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay band-4, Rs.37400-67000 plus grade pay of Rs. 8700/- or equivalent in the parent cadre or department; and

(B) possessing the following educational qualifications and experience:

(i) Certificate of Competency as Master (Foreign Going Ships) with five years experience as Deck Officer of which one year must have been in the capacity of a Master on a foreign going merchant ship.

(ii) Extra Masters Certificate of Competency with ten years of experience in survey and inspection of foreign going Merchant ships and equipments on board such ships; or

Master of Science Degree in Maritime Affairs awarded by a recognised University with twelve years of experience in survey and inspection of foreign going merchant ships and equipments on board such a ship.

Note 1: The Departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short-term contract). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.

Note 4: For the purpose of appointment on deputation (including short-term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commissions recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)			(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-			Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).
(1) Chairman or Member, Union Public Service Commission		– Chairman;	
(2) Secretary or Additional Secretary, Ministry of Shipping		– Member;	
(3) Director General of Shipping		– Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(3.) Deputy Nautical Adviser-cum-Senior Deputy Director General (Technical)	5* (2015) *(Subject to variation dependent on work load.)	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial.	Pay band - 4 Rs.37400-67000 plus grade pay of Rs. 8700/-.	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By Promotion.

11

Promotion:

Nautical Surveyor-cum-Deputy Director General (Technical) in the pay band-3, Rs. 15600-39100 plus grade pay of Rs.7600/- with five years regular service in the grade and possessing the following educational and other qualifications:

- (i) Extra Master's Certificate of Competency; or
Master of Science Degree in Maritime Affairs awarded by a recognised University.
(ii) experience of one year in capacity of a Master on a Foreign going ship.

Note 1: For acquiring educational qualification as prescribed in column 11 for promotion, the Office of Directorate General of Shipping, Ministry of Shipping shall bear the cost and facilitate the incumbents in the feeder grade post.

Note 2 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Commission.

12

13

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1) Chairman or Member, Union Public Service Commission 2) Secretary or Additional Secretary, Ministry of Shipping 3) Director General of Shipping 4) Joint Secretary In-charge of Shipping, Ministry of Shipping	Not applicable.
--	-----------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(4.) Nautical Surveyor-cum-Deputy Director General (Technical).	21* (2015) * (Subject to variation dependent on work load.)	General Central Service (Group 'A') Gazetted. Non-Ministerial.	Pay band - 3, Rs.15600-39100/- plus grade pay of Rs. 7600/-.	Not applicable.	Not exceeding 50 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

(7)	(8)
<p>Essential:</p> <p>(i) Certificate of Competency as Master of a Foreign Going Ship as recognised by the Government of India;</p> <p>(ii) five years service as Deck officer, after obtaining the certificate of competency of second mate (Foreign Going), of which one year must have been in capacity of a Master on a Foreign going ship.</p> <p>Desirable:</p> <p>(i) Extra Master's Certificate of Competency; or</p> <p>Master of Science Degree in Maritime Affairs awarded by a recognised University.</p> <p>(ii) Experience in survey and inspection of merchant ships and examination work for one year or more on the date of submission of application to the Union Public Service Commission.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note-2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Schedule Caste or the Schedule Tribe, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>	Not applicable.

(9)	(10)	(11)
One year.	<p>By direct recruitment.</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstance for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government:</p> <p>(A)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years regular service in the pay band- 3, Rs. 15600-39100/- plus grade pay- Rs. 6600/-; and</p> <p>(B) possessing the qualifications and experience as specified in column (7).</p>	Not applicable.

12	13
<p>Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <p>(1) Director General of Shipping – Chairman;</p> <p>(2) Joint Secretary-in-charge of Shipping, Ministry of Shipping – Member;</p> <p>(3) Joint Director General dealing with administration of the Directorate General of Shipping – Member.</p>	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

[No. A-12018/2/2007-MA]

C. B. SINGH, Adviser